नई राजधानी परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

नई राजधानी परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. चांदनी मरकाम

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

द्वारा प्रकाशित



अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

नई राजधानी परियोजना
छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

संस्करण : 2021
© लेखक
ISBN: 978-93-90870-01-1

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव द्वारा 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा वी.एम. ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE

प्राक्कथन

मैंने छ.ग. की राजधानी रायपुर का विकास बड़ी ही तीव्रता के साथ नगर से महानगर के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है तथा इस प्रक्रिया में जिस प्रकार से नगर के क्षेत्रफल में वृद्धि निरंतर होती ही गई तब मन में यह प्रश्न उठा कि इस क्षेत्रफल में वृद्धि होता कैसा है? तभी राजधानी में नया रायपुर परियोजना प्रारंभ किया गया, जिसके लिये रायपुर नगर से लगे हुए ग्रामों के स्थान का चुनाव किया गया जिसमें लगभग 41 ग्राम प्रभावित हुए इन ग्रामों को विस्थापित कर दिया गया।

मेरे द्वारा इस पुस्तक में विस्थापन के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के जीवन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने का प्रयास किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक में विस्थापन के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है, जिनमें प्रमुख समस्या विस्थापित परिवारों के आजीविका के निर्वहन से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालना था। अपने इस पुस्तक के माध्यम से मैंने केवल यह जानने का प्रयास किया है कि जहां–जहां विस्थापन की प्रक्रिया होती है वहां उनके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। विस्थापन के पश्चात् विस्थापित परिवारों को जिस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को इस पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक को प्रारंभ करने से लेकर अंतिम दिशा प्रदान करने तक मेरे निर्देशक **डॉ. एल.एस. गजपाल** जी का पूर्ण सहयोग मिला जिनके निर्देशन से यह पुस्तक पूर्ण हुआ, उनकी मैं सदैव आभारी रहूंगी। इस पुस्तक को पूर्ण करने में अनेक लोगों का सहयोग रहा पर सर्वाधिक मेरी माता श्रीमति **जमुना मरकाम** तथा मेरे पति श्री **गिरधर कुर्म** जी का

SAMPLE

रहा, जिन्होंने मेरी गृहस्थी की डोर संभाली तथा मुझे पुस्तक कार्य को पूर्ण करने का समय प्रदान किया जिसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ।

डॉ. चांदनी मरकाम

नमूना • SAMPLE

आभार

किसी भी कार्य के सफलता के पीछे परमपिता परमेश्वर की असीम इच्छा और आशीर्वाद होता है। कार्य की सफलता के पीछे ईश्वर भक्ति के साथ–साथ अनेक लोगों का योगदान होता है, जिन्हें हम गुरू कहते हैं। आज इस आभार प्रदर्शन के माध्यम से मैं उन समस्त लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके मार्गदर्शन तथा सहयोग के अभाव में मेरी इस पुस्तक का पूर्ण होना असंभव था।

प्रस्तुत पुस्तक की पूर्णता के लिये मैं सर्वप्रथम अपनी आराध्य देवी मां जगत्जननी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ज्ञान, बुद्धि दी जो इस पुस्तक कार्य के लिये महत्वपूर्ण है। मैं अपने पिता स्व. डी. के. मरकाम के प्रति सहृदय कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यह पुस्तक कार्य कर सकूं।

मैं अपनी माता श्रीमति जमुना देवी मरकाम की ओर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग के बिना मैं यह पुस्तक कार्य पूर्ण नहीं कर सकती थी। मैं इस पुस्तक को अपनी माता के चरणों में समर्पित करती हूँ।

मैं अपने पति श्री गिरधर कुर्म के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे पुस्तक कार्य के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया, प्रतिपल मुझे अपना सहयोग प्रदान करते रहे, साथ ही मेरी पुत्री प्रकृति एवं पुत्र प्रयाग ने भी मुझे इस पुस्तक को पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है, मेरी बड़ी दीदी मंजू नेताम की भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।

SAMPLE

मैं इस पुस्तक के निर्देशक *डॉ.एल.एस.गजपाल* एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके मार्गदर्शन से ही यह पुस्तक कार्य संभव हो पाया है, जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय तथा प्रतिपल सहयोग प्रदान किया है।

समाजशास्त्र समाजकार्य अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष *डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा* जी के प्रति अगाध कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनका मार्गदर्शन एवं सक्रिय सहयोग समय–समय पर मिलता रहा। समाजशास्त्र समाजकार्य अध्ययनशाला के आदरणीय गुरु एसोसिएट प्रोफेसर *डॉ. जे. एल.तिवारी,* एसोसिएट प्रोफेसर *डॉ. एन. कुजूर,* वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक *डॉ. हेमलता बोरकर* के प्रति है हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय व सहयोग देकर प्रस्तुत पुस्तक कार्य को आगे बढ़ाने में निःसंकोच अपने विचार दिए।

मैं समाजशास्त्र समाजकार्य अध्ययनशाला के *डॉ. राजश्री चटर्जी* सहायिका, श्री *सागर नासा* लिपिक, एवं श्री *विजय कोसरकर* की भी आभारी हूँ।

मैं अध्ययन क्षेत्र के समस्त उत्तरदाताओं की आभारी हूँ जिन्होंने अमूल्य समय एवं उचित एवं आवश्यक जानकारी प्रदान की। जो कि पुस्तक की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है।

मैं पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल एवं अन्य समस्त कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे पुस्तक से संबंधित साहित्य उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है।

चांदनी मरकाम

अनुक्रमणिका

	प्राक्कथन	*v*
	आभार	*vii*
1.	प्रस्तावना	1
2.	उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	23
3.	उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति	51
4.	विस्थापन तथा भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याएं	121
5.	पुनर्वास के सरकारी प्रयास	158
6.	विस्थापन का प्रभाव	195
7.	निष्कर्ष	235
	Bibliography	*245*

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

1

प्रस्तावना

विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न पहलुओं का समावेश है। विकास पूर्णतः न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है और न ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक प्रगति से भी संबंधित है। व्यापक अर्थों में विकास में सामाजिक आर्थिक बेहतरी के साथ–साथ सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय से भी जुड़े मुद्दे निहित होते हैं। विकास का एक दूसरा पहलू यह भी है कि विकास अपने साथ साथ अनेक समस्याओं को भी जन्म देता है। जैसे – विस्थापन, औद्योगिक प्रदूषण सामाजिक विघटन, संघर्ष इत्यादि। प्राचीन से वर्तमान समय तक समाज के लगभग प्रत्येक पहलु में परिवर्तन हुए है। विकास ऐसे परिवर्तनों को लक्षित करता है, जो प्रगति की ओर उन्मुख रहते है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, पर इसका संबंध आर्थिक पहलू से अधिक है। लेकिन विकास का समाजशास्त्र केवल आर्थिक पहलू से ही संबंधित नही है अपितु सांस्कृतिक तत्वों तथा सामाजिक संस्थाओं से भी संबंधित है।

वास्तव में विकास एक आंशिक एवं शुद्ध प्रक्रिया है जो आर्थिक पहलु में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आर्थिक जगत में विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लगाया जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य उन संबंधो तथा ढांचे से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

SAMPLE

सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज, एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता हैं। सरल शब्दों में विकास के समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैं – विकास का समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाजिक विकास से संबंधित हैं।

विकास, विस्थापन एवं जनांकिकीय प्रक्रियाएं : नगरीय विस्थापित परिवारों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय के अंतर्गत यह शोध किया गया है। इसमें नगरीय विकास की वृहद् परियोजनाओं से बढ़ते विस्थापन को दर्शाया गया है। नगरों के विकास एवं विस्तार से नगरों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। भूमि अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न एजेन्सियां कार्य करती है। इनके द्वारा नगरीय लोगों की भूमि अधिग्रहित की जाती है एवं लोगों को विस्थापित किया जाता है।

विस्थापितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनका पुनर्स्थापना करना है। इसके लिए ये एजेंसियां मुआजवा, सोलेशियम, आवासीय भूमि एवं आवास भी उपलबध कराती है, ताकि विस्थापितों का सही तरीके से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हो सके। विस्थापन से विस्थापितों को सबसे प्रमुख समस्या व्यवसाय की होती है, उनके सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों के ताने बाने के साथ ही जनांकिकीय प्रक्रियाओं में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।

विकास एवं विस्थापन

''वर्तमान में वैश्वीकरण के इस युग में विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। विस्थापन को प्रायः एक नियत कालिक घटना मान लिया जाता है, जो वास्तविक विस्थापन के बहुत पहले शुरू हो जाती है और विस्थापन के बाद लम्बे समय तक चलती रहती है।

भारतीय संविधान में ऐसा कोई एक समान पुनर्वास का कानून नहीं बना है जिससे विस्थापितों के पुनर्वास में वांछित लोगों को सहायता मिल सके। जहां भी लोगों को विस्थापित किया जाता है, वहाँ उस क्षेत्र के विस्थापितों के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है तथा विस्थापितों को दिया जाता है।

योजनाबद्ध विकास के नाम पर निजी क्षेत्र में सहयोग से त्वरित विकास की कार्यवाही हो रही है, जिसके अंतर्गत 1984 के संशोधित अधिनियमों के तहत् अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया जाता है। इसके कारण भी वृहद् पैमाने पर विस्थापन होता है। बंगाल के सिंगूर में टाटा के कारखाने के लिए, नंदीग्राम में सेज के लिए तथा अन्य क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन से हिंसक प्रतिरोध भी उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण भी बड़े शहरों के बाह्य हिस्सों में ग्रामीणों का विस्थापन सामान्य बात हो गई है।

वर्तमान में अर्थव्यवस्था आधारित विकास ने विस्थापन को स्वाभाविक मानते हुए इसकी अनदेखी ही की है, परंतु विस्थापन एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका संबंध केवल सामाजिक परिवर्तन से नहीं है, वरन् यह समुदायों की गुणवत्ता को भी काफी न्यून स्तर पर ले आता है, जिससे अलगाव तथा सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विस्थापन भी हो जाता है। नर्मदा, टिहरी, हर्सूत (मध्यप्रदेश), टिहरी (उत्तराखण्ड), जैसी वृहद् बांध परियोजनाओं में जो विस्थापन किया गया है, उसमें वास्तव में एक मानवीय समस्या उत्पन्न कर दी है। यह आर्थिक और मुआवजा क्षतिपूर्ति की समस्या से कहीं अधिक दूरगामी और विकराल है।''[1]

विकास का समाजशास्त्र

''समाजशास्त्र में विकास का समाजशास्त्र यद्यपि एक नवीन शाखा है फिर भी विकास शब्द तथा विकास प्रक्रिया का उल्लेख विभिन्न समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक विचारकों ने किया है। 'निर्धारणवाद और उन्नति' में इस शब्द का प्रयोग किया है। विकास का तात्पर्य केवल उस परिवर्तन से नहीं लगाया जाता है, जिससे कोई अप्रकट अथवा छिपी वस्तु प्रकाश में आ जाए, अपितु इसका संबंध उन्होंने संभावित परिवर्तनों से भी लगाया है। इन विचारकों का कहना है कि इन परिवर्तनों की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। उनका यह विचार था कि विकास की प्रक्रिया का अंतिम रूप ही किसी समाज को प्रगति की अवस्था तक पहुंचाता है। नैडेल (1975) के अनुसार'' विकास का समाजशास्त्र नैतिक तटस्थता को कायम रखते हुए आर्थिक तथा सामाजिक विकास का अध्ययन करेगा।''[1]

सामाजिक आर्थिक उन्नति के संस्थापक ढांचे में विकास से तात्पर्य उन्नति के उस संस्थापक ढांचे से लगाया जाता है, जो औद्योगिकवाद के कारण राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं पर परिलक्षित होती है। आर्थिक कारक ही औद्योगिकवाद को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक पहलु में होने वाले परिवर्तन को विकास के समाजशास्त्र से संबंधित माना जाता है।''[2]

विस्थापन की प्रक्रिया

''विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने मूल निवास स्थान एवं अपने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से अलग कर देती है। मूल अर्थ में जब व्यक्ति को अपने मूल निवास स्थान से दबाव डालकर हटाया जाता है तो वह विस्थापन है। जिन लोगों को अपनी आजीविका से निकाल दिया जाता है तो वे अधिक दरिद्र होते जाते है। संविधान का अनुच्छेद–21 प्रत्येक भारतीय को अपना जीवन गरिमा के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार देता है। जब सरकार की किसी परियोजना के कारण उन लोगों की आजीविका छूट जाती है, जब किसी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार एवं समाज का उत्तरदायित्व बनता है और उन लोगों का भी यह अधिकार बनता है कि वे फिर से एक नया जीवन शुरू करें जो कि उनकी सामाजिक व्यवस्था तथा आर्थिक लाभों को बनाए रख सके। परन्तु नीति बनाने वाले अर्थिक लाभ और विकास पर ज्यादा जोर देते है तथा उन लोगों के विस्थापन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर होते गए तथा गरीब लोग (जिनमें ज्यादातर स्त्रियाँ थीं) ज्यादा गरीब होते गए।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि विकास के कारण जो विस्थापन हो रहा है वह कोई आधुनिक प्रघटना नहीं है। मानवीय समाज के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ चेतनता आधुनिक समय में भी आई है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र ज्यादा पुराना नहीं है इसी प्रकार मानव अधिकार चार्टर 1948 में पारित किया गया, लेकिन इससे मूल्य कम नहीं हो जाता है (कॉकबर्न, 1993)

अंग्रेजों ने जो नीतियाँ बनाई उनका शिकार कितने लोग हुए, उन लोगों की वास्तविक संख्या तो हम नहीं जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई

नौरोजी (1988) ने बताया कि अनुमानतः 35 लाख लोगों को अपनी आजीविका से वंचित कर दिया गया। इनमें से कई लोगों को अंग्रेजों के चाय–बागानों और कारखानों में काम करने के लिए जाना पड़ा, जहाँ पर उनसे गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था।

विस्थापित का अर्थ

विस्थापित का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिनकी भूमि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक निश्चित तिथि को या इससे पहले निरन्तर रूप से निर्माण कार्य हेतु अवाप्त की जा रही हो। विस्थापित में वे खातेदार या सह–खातेदार भी शामिल होते हैं जिनकी जमीन या मकान का कोई भाग भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के अन्तर्गत आ गया हो। इस संबंध में तीन प्रकार के विस्थापितों का उल्लेख किया जाता है।

विस्थापित कृषक

ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खेतों पर निर्भर हैं एवं जो स्थायी रूप से अपने जन्म स्थान पर रह रहे हों। विस्थापित में वे खातेदार या सहखातेदार भी शामिल होंगे, जिनकी जमीन या मकान का कोई भाग भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के अंतर्गत आ गया हो।

विस्थापित अकृषक

ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर अथवा ग्रामीण दस्तकार जो कि बांधों के निर्माण या शहरी विस्तार विकास योजनाओं के कारण अधिग्रहण किए जा रहे क्षेत्र के अंतर्गत स्थायी रूप से अपने जन्म स्थान पर रह रहे हों एवं अधिग्रहीत की जा रही सम्पत्ति में कोई आर्थिक हित रखते हों।

विस्थापित निवासी

ऐसे व्यक्ति जो विस्थापित कृषक एवं अकृषक के अंतर्गत नहीं आते हों लेकिन जन्म से ही वे अपने मूल निवास स्थान पर अधिग्रहीत किए जाने वाले क्षेत्र पर रह रहे हों।

एक और दृष्टिकोण से विस्थापन के दो मुख्य प्रकार हैं : स्वैच्छिक विस्थापन एवं अस्वैच्छिक विस्थापन। स्वैच्छिक विस्थापन में व्यक्ति अपना जन्म स्थान अपनी स्वेच्छा से छोड़ता है एवं अस्वैच्छिक विस्थापन में व्यक्ति को अपने मूल निवास या जन्म स्थान से दबाव से हटाया जाता है।"[3]

विस्थापन

विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से हटना अर्थात् जब कोई व्यक्ति या समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते है। किसी राज्य में विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सबसे बड़ी समस्या के रूप में विस्थापन उभर कर सामने आता है। किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उस स्थान पर रहने व बसने वाले जनसंख्या को किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाता हैं, तो इस प्रक्रिया को हम "विस्थापन" कहते है।

विकास और विस्थापन का गहरा संबंध है, भारत में विस्थापन और विकास साथ–साथ चलने वाली प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक कभी बांध निर्माण के कारण, कभी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, तो कभी राजधानी निर्माण के लिए जनसंख्या के एक बड़े भाग का विस्थापन होता रहा है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रभावित होता रहा है। प्रस्तुत अध्ययन विस्थापन के फलस्वरूप जनसंख्या पर होने वाले प्रभाव के समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक प्रयास है, जिससे कि हम किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

अध्ययन विषय का समाजशास्त्रीय महत्व

विकासशील राज्यों में अपने राज्य के विकास के लिए छोटे–छोटे गांवों को विस्थापित किया जाता है तो उनके जीवन पर विस्थापन के कारण पड़ने वाले प्रभाव को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। विकास और विस्थापन समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विस्थापन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ावा मिला। विभिन्न शोध अध्ययन इस तथ्य पर प्रकाश ड़ालता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम चार दशकों मे जितने भी विस्थापन हुए उनमे अधिकांश हमारी विकास संबंधी जरूरतों, जिसमे बांध और औद्योगिक इकाई के विकास से संबंधित रहे है और यह भी सच है कि इससे सबसे ज्यादा जनजातिय समाज प्रभावित हुआ है। जनजातिय विकास मंत्रालय की रिपोर्ट 2008 यह दर्शाता है कि देश में हुए कुल विस्थापनों में 40 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है क्योंकि ज्यादातर बांध व औद्योगिक इकाईयों की स्थापना जनजातिय क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं।

समाजशास्त्रीय संदर्भ मे जब हम विस्थापन के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं तो मुख्य रूप से जो बातें उभरकर सामने आती है, उनमे भावनात्मक रूप से अपने मूल निवास से पृथक होना, अन्तः पारिवारिक तथा अन्तः सामुदायिक संबंधो मे बिखराव होना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, असुरक्षा, बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हे विस्थापन की देन कह सकते है, इस विषय मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विस्थापन से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे ही होते है। प्रस्तुत अध्ययन में इन तथ्यों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

छ.ग. राज्य पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में पहली बार प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान मे रखते हुए पृथक रूप से नई राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत् जिस स्थान पर नया राजधानी क्षेत्र विस्तृत करने का निर्णय हुआ है, उससे कुल 41 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें 27 गांव को राज्यशासन ने वास्तविक प्रभावित गांव की सूची मे रखा है। प्रस्तुत अध्ययन समाजशास्त्रीय संदर्भ में विस्थापन के फलस्वरूप इन समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जिससे कुछ नये तथ्य समाजशास्त्रीय संदर्भ में ज्ञात हुए हैं जो कि अध्ययन की प्रासंगिकता को बढ़ाता है।

पूर्व में किए गए शोध अध्ययनों का पुनरावलोकन

आंकड़ो के मुताबिक आजादी से लेकर अब तक 3,81,500 लोग और 76,300 परिवार विकास के नाम पर विस्थापित किए गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इनमें वे राज्य हैं जहां जनजातिय सदियों से रहते आये है। आंकड़े बताते है कि झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से सबसे ज्यादा संपन्न है, वहां विस्थापन सबसे ज्यादा हुआ है। दरअसल विस्थापन का संबंध सीधे आधुनिक विकास से है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश से आजादी के इतने सालों बाद भी लाखों की तादाद में लोगों को विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है, पर आज उनकी हालत जैसे के तैसे बनी हुई है, चाहे वह "नर्मदा बांध परियोजना" से विस्थापित हुए लोग हो या किसी अन्य औद्योगिक इकाई के कारण विस्थापित लोग। प्रस्तुत शोध विषय पर किए गये महत्वपूर्ण शोध अध्ययनों की समीक्षा निम्न हैं–

जिस्ट एवं फोवा (1934)[4] के अनुसार विस्थापन के पश्चात् अधिकांश लोगों का अभिमत है कि मलिन बस्तियों में अपकर्षित आवास एवं प्रतिवेश न केवल बस्तियों में व्यक्तित्व को दबाते हैं अपितु बाल अपराध एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के साथ बुरे स्वास्थ्य को भी जन्म देते हैं।

लुइस विनिक (1952)[5] का भी मानना है कि विस्थापन के पश्चात् अत्यधिक भीड एवं एकान्तता के अभाव के कारण महिलाओं में भावनात्मक एवं मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी क्षय रोग से ग्रसित हो जाती है।

विद्यार्थी (1968)[6] ने बिहार के औद्योगिक क्षेत्र हटिया के निकट 8 जनजाति गांवों के अध्ययन में इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि औद्योगिक केन्द्र खुलने के बाद भी जनजातिय समुदाय परम्परागत कृषि जन्य व्यवस्था पर ही निर्भर है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है।

Fernandes, Das and Rao (1989)[7] ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में बांध निर्माण के नाम पर अनेक प्रकार के विस्थापन हुए हैं, लगभग 21 मिलियन लोगों का विस्थापन बांध परियोजना के कारण हुआ है। इसके पश्चात् श्री एन.सी. सक्सेना ने अपने शोध से यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास नियम के अंतर्गत बड़े बांध निर्माण में लगभग अभी तक 40 मिलियन लोगो का विस्थापन हो चुका है।

बर्मन बी. के. रॉय (1990)[8] ने भारत की जनजाति महिलाओं तथा विकास की चुनौतियो पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला हैं कि समाज में परंपरागत शिक्षा जनजातिय महिलाओं के विकास हेतु पर्याप्त नही है, इसके लिए समय–समय पर कल्याणकारी योजनाओं को शिविरो के माध्यम से संचालित करते हुए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

Gibbons and katz (1991) [9] का अध्ययन विस्थापित मजदूरों पर आधारित रहा है। उन्होंने विस्थापन के तीन प्रमुख कारण बताये है पहला– पहले से करते हुए काम से अलग होना वह भी अनैच्छिक। दूसरा–विस्थापित मजदूरों का काम से अलग होना स्थाई है, अस्थाई नही, इसका तात्पर्य है कि वह अपने पुराने कार्य मे पुनः वापस नही आ सकते है। तीसरा– प्रत्येक मजदूर का कार्य से अलग होने के लिए कार्य प्रदर्शन असंबंधित होना है।